



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I-खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 149]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 1968/श्रावण 2, 1890

No. 149]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 1968/SRAVANA 2, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1968

संकल्प

विषय.—शिक्षा की राष्ट्रीय नीति

सं० एफ० 30-60/67-आई० यू०.—भारतीय समाज में शिक्षा को हमेशा से ही मान्य स्थान दिया जाता रहा है। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के महान् नेता शिक्षा के बुनियादी योगदान से परिचित थे और राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में उसके असामान्य महत्व पर जोर देते थे। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की योजना बनाई थी, जिसका उद्देश्य मानसिक और शारीरिक कार्यों में सामंजस्य पैदा करना था। शिक्षा को लोगों के जीवन के साथ सीधे सम्बद्ध करने के लिए उठाया गया यह एक महान् कदम था। इसी प्रकार स्वतंत्रता से पहले अन्य अनेक नेताओं ने भी राष्ट्रीय शिक्षा में अत्यन्त महत्वपूर्ण योग दिया था।

2. स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार और राज्य सरकारें, राष्ट्रीय प्रगति और सुरक्षा के प्रभावी साधन के रूप में शिक्षा पर अधिकाधिक ध्यान देती रही हैं। अनेक आयोगों और समितियों ने, जिनमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) और माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) उल्लेखनीय हैं, शैक्षिक पुनर्निर्माण की समस्याओं की समीक्षा की। इन आयोगों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए गए और जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में विज्ञान-नीति पर संकल्प पारित होने के बाद विज्ञान, शिल्पविज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास पर विशेष बल दिया जाता रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम चरण में इस बात की जरूरत महसूस की गई कि शिक्षा व्यवस्था का सविस्तार पुनरीक्षण किया जाए जिससे शैक्षिक पुनर्निर्माण के लिए नए सिरे से तथा और बृढ़ निश्चय के साथ प्रयत्न किया जा सके, और "शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप, तथा सभी स्तरों और पहलुओं पर शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धान्तों और नीतियों" पर सरकार को सलाह देने के लिए शिक्षा आयोग (1964-66) की नियुक्ति की गई। अब तक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट पर काफी चर्चा हुई है और टिप्पणियां की गई हैं। सरकार को इस बात की प्रसन्नता है कि इन चर्चाओं से शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में मतैक्य हो गया है।

3. भारत सरकार का यह विश्वास है कि देश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय एकता तथा समाजवादी समाज के निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा आयोग द्वारा बताई गई स्थूल रूपरेखाओं के आधार पर शिक्षा का पुनर्निर्माण आवश्यक है। इस हेतु शिक्षा को लोगों के जीवन के अधिक निकट लाने के लिए शिक्षा प्रणाली का रूपान्तरण, शैक्षिक अवसरों के विस्तार के लिए लगातार प्रयत्न, सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणता में सुधार करने के लिए लगातार और व्यापक प्रयत्न, विज्ञान और शिल्पविज्ञान के विकास पर विशेष बल, तथा नैतिक और सामाजिक मूल्यों का निर्माण करना होगा। शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय सेवा और विकास के लिए कृतसंकल्प, चरित्र-सम्पन्न और योग्य युवक और युवतियों का निर्माण हो। सभी शिक्षा राष्ट्रीय विकास कर सकती है, सामान्य नागरिकता और संस्कृति की भावना पैदा कर सकती है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बना सकती है। विश्व के राष्ट्रों में इस देश को उसकी महान सांस्कृतिक विरासत और उसकी असामान्य सामर्थ्य के अनुरूप योग्य स्थान दिलाने के लिए यह आवश्यक है।

4. अतः भारत सरकार निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर देश में शिक्षा का विकास करने के लिए संकल्प करती है :—

(1) निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा.—चौदह वर्ष तक की वय के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 45 के अधीन दिए निवेशक सिद्धान्तों को अमल में लाने के लिए अग्रपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। स्कूलों में चालू व्यर्थता और अगति को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल में दाखिल हर छात्र विहित पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर ले, उपयुक्त कार्यक्रमों का विकास किया जाना चाहिए।

(2) अध्यापकों का दर्जा, वेतन-भत्ते और शिक्षा.—(क) शिक्षा की गुणता और राष्ट्रीय विकास में उसके योगदान के लिए उत्तरदायी कारणों में से अध्यापक निस्सन्देह सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। उसके व्यक्तिगत गुणों और चरित्र, शैक्षिक योग्यताओं एवं व्यवसायिक अर्हताओं पर अतः शिक्षा सम्बन्धी सभी प्रयत्नों

की सफलता निर्भर है। अतः अध्यापकों को समाज में एक सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। उनकी योग्यताओं और उनके उत्तरदायित्वों को देखते हुए उनके वेतन-भत्ते तथा अन्य सेवा की शर्तें पर्याप्त और सन्तोषजनक होनी चाहिए।

(ख) स्वतंत्र अध्ययन तथा अनुसंधान सम्बन्धी प्रबन्ध प्रकाशित करने तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भाषण करने और लिखने की अध्यापकों की शैक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए।

(ग) अध्यापक शिक्षा, विशेष रूप से अन्तर्संवा शिक्षा, पर यथोचित बल दिया जाना चाहिए।

(3) भाषाओं का विकास: (क) प्रादेशिक भाषाएं.—भारतीय भाषाओं और साहित्य का उत्साह के साथ विकास करना शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास की एक अनिवार्य शर्त है। जब तक यह नहीं किया जाएगा, लोगों की सृजनात्मक शक्तियां क्रियाशील नहीं होंगी, शिक्षा के स्तरों में सुधार नहीं आएगा, जनसाधारण तक ज्ञान नहीं पहुंचेगा, और बुद्धिजीवियों तथा जनसाधारण के बीच की खाई यदि खड़ी न भी हुई तो यथावत् बनी रहेगी। प्राथमिक और माध्यमिक अवस्थाओं में प्रादेशिक भाषाओं को पहले से ही शिक्षा के माध्यम के रूप में व्यवहृत किया जा रहा है। अब उनका प्रयोग विश्वविद्यालय अवस्था में भी करने के लिए तेजी से कदम उठाए जाने चाहिए।

(ख) त्रिभाषा सूत्र.—माध्यमिक अवस्था में राज्य सरकारों को त्रिभाषा सूत्र लागू करना और जोर-शोर के साथ उसको क्रियान्वित करना चाहिए। इस सूत्र के अन्तर्गत एक आधुनिक भारतीय भाषा तरजीह, एक दक्षिण भारतीय भाषा, का अध्ययन तथा साथ ही हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी और अंग्रेजी और अहिन्दी भाषी राज्यों में प्रादेशिक भाषा तथा अंग्रेजी के साथ हिन्दी का अध्ययन शामिल है। विश्वविद्यालयों और कालेजों में हिन्दी तथा/या अंग्रेजी के उपयुक्त पाठ्यक्रमों की सुविधा भी होनी चाहिए ताकि छात्र विहित विश्वविद्यालय मानकों के अनुरूप इन भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त कर सकें।

(ग) हिन्दी.—हिन्दी के विकास और प्रसार का हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का विकास करते समय इस बात का समुचित ध्यान रखना चाहिए कि यह भाषा संविधान के अनुच्छेद 351 के उपबन्धों के अनुसार भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकेगी। अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने वाले कालेजों तथा उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थाओं को स्थापित करने के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

(घ) संस्कृत.—भारतीय भाषाओं के विकास में संस्कृत के विशेष महत्व को देखते हुए और देश की सांस्कृतिक एकता के लिए उसके अपूर्व योगदान की दृष्टि से स्कूल तथा विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत के अध्यापन की सुविधाएं अधिक

विस्तृत पैमाने पर दी जानी चाहिए। इस भाषा के अध्यापन के नए तरीकों के विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए और प्रथम और द्वितीय डिग्री अवस्थाओं पर, उन पाठ्यक्रमों में जहाँ कि इस भाषा का ज्ञान उपयोगी है (जैसे, आधुनिक भारतीय भाषाएं, प्राचीन भारतीय इतिहास, भारत विद्या तथा भारतीय दर्शन) संस्कृत के अध्यापन की सम्भावनाओं की खोज की जानी चाहिए।

(ङ) **अन्तर्राष्ट्रीय भाषाएं**.—अंग्रेजी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। संसार में ज्ञान का प्रसार बड़ी तेजी से हो रहा है, विशेषकर विज्ञान और शिल्पविज्ञान के क्षेत्र में। भारत को न केवल इस विकास को बनाए रखना है बल्कि अपनी ओर से भी उसमें सार्थक योगदान करना है। इस उद्देश्य से अंग्रेजी के अध्ययन को विशेष रूप से पुष्ट करना चाहिए।

(4) **शिक्षा के अवसरों का समानीकरण**.—शिक्षा की समस्याओं के समानीकरण के लिए श्रमपूर्वक प्रयत्न किए जाने चाहिए।

(क) शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था की दृष्टि से प्रादेशिक असंतुलन को मिटाना चाहिए तथा ग्रामीण और अन्य पिछड़े इलाकों में शिक्षा की अच्छी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

(ख) सामाजिक एकता तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा आयोग की सिफारिशों में बताई गई समान स्कूल पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। सामान्य स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। पब्लिक स्कूलों के समान विशेष स्कूलों में छात्रों का दाखिला योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए और सामाजिक वर्गों के पृथक्करण को बचाने के लिए फीस-भागी का अनुपात विहित कर देना चाहिए। परन्तु इससे संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) न केवल सामाजिक न्याय की दृष्टि से बल्कि सामाजिक रूपान्तरण की गति को तीव्र करने के लिए भी लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए।

(घ) पिछड़े वर्गों तथा विशेष रूप से आदिम जातियों में शिक्षा का विकास करने के लिए अधिक तीव्र प्रयत्नों की आवश्यकता है।

(ङ) विकलांगों और मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विकास करना चाहिए और ऐसे समन्वित कार्यक्रमों का विकास किया जाना चाहिए जिसके द्वारा ये बच्चे नियमित स्कूलों में अध्ययन प्राप्त कर सकें।

- (5) **प्रतिभा की पहचान.**—प्रवीणता का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं उनकी छोटी से छोटी उम्र में खोज निकालना चाहिए और उनके विकास के लिए हर सम्भव प्रोत्साहन और अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ।
- (6) **कार्यानुभव और राष्ट्रीय सेवा.**—परस्पर सेवा और सहायता के उपयुक्त कार्य-क्रमों द्वारा स्कूलों और समुदायों को एक दूसरों के निकट लाना चाहिए । तदनुसार कार्यानुभव तथा राष्ट्रीय सेवा, जिसमें सामुदायिक सेवा तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के सार्थक तथा चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम भी शामिल हैं, शिक्षा का अभिन्न अंग होने चाहिए । इन कार्यक्रमों में स्वावलम्बन, चरित्र-निर्माण तथा सामाजिक उद्देश्यों के लिए आत्मोत्सर्ग की भावना का विकास आदि पर बल दिया जाना चाहिए ।
- (7) **विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान.**—राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति को बढ़ाने के लिए विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । स्कूल अवस्था के अन्त तक विज्ञान और गणित सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग होने चाहिए ।
- (8) **कृषि तथा उद्योग की शिक्षा.**—कृषि तथा उद्योग सम्बन्धी शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए ।
- (क) प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए । जहां तक हो सके ये विश्वविद्यालय एक अट्टाने में स्थित स्वतःपूर्ण होने चाहिए; पर जहां आवश्यक हो इनके विभिन्न अट्टानों में स्थित संघटक कालेज भी हो सकते हैं । अन्य विश्वविद्यालयों में भी जहां आवश्यक संभावनाएं हैं कृषि के एक या उससे अधिक पहलुओं के अध्ययन के लिए पुष्टा विभाग खोले जाने चाहिए ।
- (ख) तकनीकी शिक्षा में, उनके एक अभिन्न अंग के रूप में, उद्योगों से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । तकनीकी शिक्षा तथा अनुसंधान का सम्बन्ध उद्योग से बहुत निकट का होना चाहिए ताकि एक से दूसरे में कार्मिक आ जा सकें, और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सुविधाओं की व्यवस्था, रूपरेखा तैयार करने तथा आवधिक समीक्षा के लिए व्यवस्था हो सके ।
- (ग) देश की औद्योगिक, कृषि तथा अन्य तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकताओं की निरन्तर समीक्षा होती रहनी चाहिए तथा शिक्षा संस्थाओं से निकले छात्रों तथा रोजगार के अवसरों के बीच उचित संतुलन बनाए रखने के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जाने चाहिए ।

- (9) **पुस्तकों का उत्पादन.**—प्रोत्साहन तथा पारिश्रमिक की उदार नीति के द्वारा श्रेष्ठतम लेखकों को आकर्षित करके पुस्तकों की गुणता में सुधार किया जाना चाहिए। स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए उच्च-स्तर की पाठ्यपुस्तकें प्राप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। बार-बार पाठ्यपुस्तकें बदलने से बचना चाहिए और इन पुस्तकों का मूल्य इतना होना चाहिए कि मामूली हैसियत का छात्र भी उन्हें खरीद सके।

व्यावसायिक पैमाने पर स्वायत्त पुस्तक निगमों की स्थापना की सम्भावनाओं की परीक्षा की जानी चाहिए और कुछ ऐसी बुनियादी पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए जो देश भर के लिए समान हों। बच्चों की पुस्तकों और प्रादेशिक भाषाओं की विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

- (10) **परीक्षाएं.**—परीक्षा सुधारों का एक प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि परीक्षाओं की विश्वसनीयता और उनकी मान्यता में सुधार हो सके और मूल्यांकन एक ऐसी निरन्तर प्रक्रिया हो जिसका लक्ष्य छात्र को उपलब्धि के स्तर को उन्नत करने में सहायता देना, होना चाहिए न कि समय-विशेष में उसके कार्य की गुणता को देख कर उसे 'प्रमाणपत्र' दे देना।

- (11) **माध्यमिक शिक्षा :** (क) माध्यमिक (तथा उच्चतर) स्तर पर शिक्षा के अवसर सामाजिक परिवर्तन तथा रूपान्तरण का एक प्रमुख उपकरण है। अतएव माध्यमिक शिक्षा की सुविधाएं तेजी से उन क्षेत्रों और वर्गों को भी दी जानी चाहिए जिनको आज तक यह प्राप्त नहीं हो सकीं।

(ख) इस अवस्था पर तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था मोटे तौर पर विकासमान अर्थव्यवस्था तथा वास्तविक रोजगार अवसरों के अनुरूप होनी चाहिए। तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर प्रभावी रूप से समापक बनाने के लिए यह सम्बन्ध आवश्यक है। तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं का उपयुक्त रूप से विशाखन किया जाना चाहिए ताकि उसके अन्तर्गत अनेक क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य, चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य, गृह-प्रबन्ध, कला और शिल्प, अनुसन्धानीय प्रशिक्षण, आदि आ सकें।

- (12) **विश्वविद्यालय शिक्षा :** (क) एक कालेज या विश्वविद्यालय में कितने पूर्ण-कालिक छात्र भर्ती किए जाएं इस की संख्या प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा अन्य सुविधाओं और कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए निश्चित की जानी चाहिए।

- (ख) नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता है। उनकी स्थापना तभी की जानी चाहिए जब पर्याप्त मात्रा में निधि उपलब्ध हो तथा उपयुक्त मानकों के बनाए रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई हो।
- (ग) इस स्तर पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और साथ ही प्रशिक्षण और अनुसंधान के मानकों में सुधार करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
- (घ) उच्च शिक्षा के केन्द्रों की सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए और कुछ थोड़े से ऐसे 'केन्द्र स्कूल' स्थापित किए जाने चाहिए जिनका उद्देश्य अनुसंधान और प्रशिक्षण में उच्चतम मानक स्थापित करना हो।
- (ङ) विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को सामान्यतया अधिक बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। जहां तक हो सके अनुसंधान की संस्थाएं विश्वविद्यालय के अन्तर्गत ही कार्य करें अथवा उनके साथ निकट सम्पर्क रखें।
- (13) **अल्पकालिक शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम.**—अल्पकालिक शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय स्तर पर बड़े पैमाने पर विकसित किए जाने चाहिए। यही सुविधाएं माध्यमिक स्कूल के छात्रों, अध्यापकों तथा औद्योगिक, कृषि सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार के कर्मचारियों के लिए भी दी जानी चाहिए। अल्पकालिक तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को वही दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए जो कि पूर्णकालिक शिक्षा को। इस प्रकार की सुविधाओं से स्कूल से रोजगार की ओर जाने में आराम रहेगा, शिक्षा के हित को बढ़ावा मिलेगा तथा उन बहुत से लोगों को अवसर भी मिल सकेगा जो आगे की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं पर पूर्णकालिक आधार पर नहीं कर सकते।
- (14) **सज्जा तथा प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार.**—(क) लोक निरक्षरता को दूर करना आवश्यक है। यह केवल लोकतंत्रीय संस्थाओं के कार्य में भाग लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा कार्यक्रमों की गति तीव्र करने के लिए (विशेषकर कृषि के क्षेत्र में) ही नहीं बल्कि सामान्य राष्ट्रीय विकास की गति को तीव्र करने के लिए भी आवश्यक है। बड़ी वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा अन्य संस्थापनाओं के कर्मचारियों को जितनी जल्दी हो सके कामचलाऊ रूप से साक्षर बनाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य में मार्गदर्शन सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को करना चाहिए, अध्यापकों और छात्रों को सक्रिय रूप से साक्षरता अभियानों का संगठन करना चाहिए, विशेष रूप से सामाजिक तथा राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रमों के रूप में।
- (ख) युवा कृषकों की शिक्षा तथा स्वनियोजन के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने पर विशेष बल देना चाहिए।

(15) खेलकूद.—खेलकूद का विकास बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए और इसका उद्देश्य शीघ्रतः विद्यार्थी तथा इस क्षेत्र में प्रवीणता दिखाने वाले व्यक्तियों के लिए उनकी शारीरिक योग्यता और खेलकारी को उत्पन्न करने के लिए किया जाना चाहिए। जहाँ पर खेल के मैदानों तथा अखिल राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के विकास की अन्य सुविधाएँ नहीं हैं, वहाँ ये सुविधाएँ प्राथमिकता के आधार पर दी जानी चाहिए।

(16) अल्पसंख्यकों की शिक्षा.—न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बल्कि उनकी शैक्षिक अभिरुचि को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों के सम्मेलन में अगस्त, 1961 में एक वक्तव्य जारी किया गया था।

(17) शिक्षा का ढाँचा.—यह आवश्यक है कि देश के हर भाग में शिक्षा का ढाँचा मोटे तौर पर एक समान हो। इसका उद्देश्य अन्ततः 10 + 2 + 3 पैटर्न को अपनाना होना चाहिए, इसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार दो वर्ष की उच्चतर माध्यमिक अवस्था या तो स्कूलों में हो या कॉलेजों में या दोनों में हो।

5. ऊपर बताई गई रूपरेखा के अनुसार शिक्षा का पुनर्गठन करने में अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। उद्देश्य यह होना चाहिए कि धीरे-धीरे शिक्षानिवेश को बढ़ाया जाए ताकि जितनी जल्दी हो सके वह राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत खर्च के स्तर पर पहुँच जाए।

6. भारत सरकार इस बात को मानती है कि शिक्षा का पुनर्निर्माण सरल काम नहीं है। न केवल साधनों की कमी है, बल्कि समस्याएँ अत्यधिक जटिल हैं। यह देखते हुए कि शिक्षा विज्ञान तथा अनुसंधान भौतिक तथा जनसाधनों के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों का बीड़ा उठाने के अतिरिक्त राज्य सरकारों को राष्ट्रीय महत्व के उन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता देगी जहाँ राज्यों और केन्द्र के समन्वित प्रयत्नों की आवश्यकता है।

7. भारत सरकार हर पांच वर्ष में प्रगति की समीक्षा करेगी और आगे के विकास के लिए मार्गदर्शक सुझाव देगी।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों तथा संघीय राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जी० के० चन्द्रीरमानी,
सचिव, भारत सरकार।

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi, the 24th July, 1968

RESOLUTION

SUBJECT:—*National Policy on Education*

No. F. 30-60/67-IU.—Education has always been accorded an honoured place in Indian society. The great leaders of the Indian freedom movement realised the fundamental role of education and throughout the nation's struggle for independence, stressed its unique significance for national development. Gandhiji formulated the scheme of basic education seeking to harmonize intellectual and manual work. This was a great step forward in making education directly relevant to the life of the people. Many other national leaders likewise made important contributions to national education before independence.

2. In the post-independence period, a major concern of the Government of India and of the States has been to give increasing attention to education as a factor vital to national progress and security. Problems of educational reconstruction were reviewed by several Commissions and Committees, notably the University Education Commission (1948-49) and the Secondary Education Commission (1952-53). Some steps to implement the recommendations of these commissions were taken; and with the passing of the Resolution on Scientific Policy under the leadership of Jawaharlal Nehru, the development of science, technology and scientific research received special emphasis. Towards the end of the Third Five Year Plan, a need was felt to hold a comprehensive review of the educational system with a view to initiating a fresh and more determined effort at educational reconstruction; and the Education Commission (1964-66) was appointed to advise Government on "the national pattern of education and on the general principles and policies for the development of education at all stages and in all aspects." The Report of the Education Commission has since been widely discussed and commented upon. Government is happy to note that a general consensus on the national policy on education has emerged in the course of these discussions.

3. The Government of India is convinced that a radical reconstruction of education on the broad lines recommended by the Education Commission is essential for economic and cultural development of the country, for national integration and for realising the ideal of a socialist pattern of society. This will involve a transformation of the system to relate it more closely to the life of the people; a sustained and intensive effort to raise the quality of education at all stages; an emphasis on the development of science and technology; and the cultivation of moral and social values. The educational system must produce young men and women of character and ability committed to national service and development. Only then will education be able to play its vital role in promoting national progress, creating a sense of common citizenship and culture, and strengthening national integration. This is necessary if the country is to attain its rightful place in the comity of nations in conformity with its great cultural heritage and its unique potentialities.

4. The Government of India accordingly resolves to promote the development of education in the country in accordance with the following principles:—

(1) *Free and Compulsory Education*.—Strenuous efforts should be made for the early fulfilment of the Directive Principle under Article 45 of the Constitution seeking to provide free and compulsory education for all children up to the age of 14. Suitable programmes should be developed to reduce the prevailing wastage and stagnation in schools and to ensure that every child who is enrolled in school successfully completes the prescribed course.

(2) *Status, Emoluments and Education of Teachers*.—(a) Of all the factors which determine the quality of education and its contribution to national development, the teacher is undoubtedly the most important. It is on his personal qualities and character, his educational qualifications and professional competence that the success of all educational endeavour must ultimately depend. Teachers must therefore be accorded an honoured place in society. Their emoluments and other service conditions should be adequate and satisfactory having regard to their qualifications and responsibilities.

(b) The academic freedom of teachers to pursue and publish independent studies and researches and to speak and write about significant national and international issues should be protected.

(c) Teacher education, particularly in-service education, should receive due emphasis.

(3) *Development of Languages*: (a) *Regional Languages*.—The energetic development of Indian languages and literature is a *sine qua non* for educational and cultural development. Unless this is done, the creative energies of the people will not be released, standards of education will not improve, knowledge will not spread to the people, and the gulf between the intelligentsia and the masses will remain, if not widen further. The regional languages are already in use as media of education at the primary and secondary stages. Urgent steps should now be taken to adopt them as media of education at the university stage.

(b) *Three-Language Formula*.—At the secondary stage, the State Governments should adopt, and vigorously implement, the three-language formula which includes the study of a modern Indian language, preferably one of the southern languages, apart from Hindi and English in the Hindi-speaking States, and of Hindi along with the regional language and English in the non-Hindi speaking States. Suitable courses in Hindi and/or English should also be available in universities and colleges with a view to improving the proficiency of students in these languages up to the prescribed university standards.

(c) *Hindi*.—Every effort should be made to promote the development of Hindi. In developing Hindi as the link language, due care should be taken to ensure that it will serve, as provided for in Article 351 of the Constitution, as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India. The establishment, in non-Hindi States, of colleges and other institutions of higher education which use Hindi as the medium of education should be encouraged.

(d) *Sanskrit*.—Considering the special importance of Sanskrit to the growth and development of Indian languages and its unique contribution to the cultural unity of the country, facilities for its teaching at the school and university stages should be offered on a more liberal scale. Development of new methods of teaching the language should be encouraged, and the possibility explored of including the study of Sanskrit in those courses (such as modern Indian languages, ancient Indian history, Indology and Indian philosophy) at the first and second degree stages, where such knowledge is useful.

(e) *International Languages*.—Special emphasis needs to be laid on the study of English and other international languages. World knowledge is growing at a tremendous pace, especially in science and technology. India must not only keep up with this growth but should also make her own significant contribution to it. For this purpose, the study of English deserves to be specially strengthened.

(4) *Equalisation of Educational Opportunity*.—Strenuous efforts should be made to equalise educational opportunity.

(a) Regional imbalances in the provision of educational facilities should be corrected and good educational facilities should be provided in rural and other backward areas.

(b) To promote social cohesion and national integration, the Common School System as recommended by the Education Commission should be adopted. Efforts should be made to improve the standard of education in general schools. All special schools like Public Schools should be required to admit students on the basis of merit and also to provide a prescribed proportion of free-studentships to prevent segregation of social classes. This will not, however, affect the rights of minorities under Article 30 of the Constitution.

(c) The education of girls should receive emphasis, not only on grounds of social justice, but also because it accelerates social transformation.

(d) More intensive efforts are needed to develop education among the backward classes and especially among the tribal people.

(e) Educational facilities for the physically and mentally handicapped children should be expanded and attempts should be made to develop integrated programmes enabling the handicapped children to study in regular schools.

(5) *Identification of Talent*.—For the cultivation of excellence, it is necessary that talent in diverse fields should be identified at as early an age as possible, and every stimulus and opportunity given for its full development.

(6) *Work-Experience and National Service*.—The school and the community should be brought closer through suitable programmes of mutual service and support. Work-experience and national service including participation in meaningful and challenging programmes of community service and national reconstruction should accordingly become an integral part of education. Emphasis in these programmes should be on self-help, character formation and on developing a sense of social commitment.

(7) *Science Education and Research*.—With a view to accelerating the growth of the national economy, science education and research should receive high priority. Science and mathematics should be an integral part of general education till the end of the school stage.

(8) *Education for Agriculture and Industry*.—Special emphasis should be placed on the development of education for agriculture and industry.

(a) There should be at least one agricultural university in every State. There should, as far as possible, be single campus universities; but where necessary, they may have constituent colleges on different campuses. Other universities may also be assisted, where the necessary potential exists, to develop strong departments for the study of one or more aspects of agriculture.

(b) In technical education, practical training in industry should form an integral part of such education. Technical education and research should be related closely to industry, encouraging the flow of personnel both ways and providing for continuous co-operation in the provision, design and periodical review of training programmes and facilities.

(c) There should be a continuous review of the agricultural, industrial and other technical manpower needs of the country and efforts should be made continuously to maintain a proper balance between the output of the educational institutions and employment opportunities.

(9) *Production of Books*.—The quality of books should be improved by attracting the best writing talent through a liberal policy of incentives and remuneration. Immediate steps should be taken for the production of high quality text-books for schools and universities. Frequent changes of text-books should be avoided and their prices should be low enough for students of ordinary means to buy them. The possibility of establishing autonomous book corporations on commercial lines should be examined and efforts should be made to have a few basic text-books common throughout the country. Special attention should be given to books for children and to university level books in regional languages.

(10) *Examinations*.—A major goal of examination reforms should be to improve the reliability and validity of examinations and to make evaluation a continuous process aimed at helping the student to improve his level of achievement rather than at 'certifying' the quality of his performance at a given moment of time.

(11) *Secondary Education*.—(a) Educational opportunity at the secondary (and higher) level is a major instrument of social change and transformation. Facilities for secondary education should accordingly be extended expeditiously to areas and classes which have been denied these in the past.

(b) There is need to increase facilities for technical and vocational education at this stage. Provision of facilities for secondary and vocational education should conform broadly to requirements of the developing economy and real employment opportunities. Such linkage is necessary to make technical and vocational education at the secondary stage effectively terminal. Facilities for technical and vocational education should be suitably diversified to cover a large number of fields such as agriculture, industry, trade and commerce, medicine and public health, home management, arts and crafts, secretarial training, etc.

(12) *University Education.*—(a) The number of whole-time students to be admitted to a college or university department should be determined with reference to the laboratory, library and other facilities and to the strength of the staff.

(b) Considerable care is needed in establishing new universities. They should be started only after an adequate provision of funds has been made for the purpose and due care has been taken to ensure proper standards.

(c) Special attention should be given to the organization of post-graduate courses and to the improvement of standards of training and research at this level.

(d) Centres of advanced study should be strengthened and a small number of 'clusters of centres' aiming at the highest possible standard in research and training should be established.

(e) There is need to give increased support to research in universities generally. The institutions for research should, as far as possible, function within the fold of universities or in intimate association with them.

(13) *Part-time Education and Correspondence Courses.*—Part-time education and correspondence courses should be developed on a large scale at the university stage. Such facilities should also be developed for secondary school students, for teachers and for agricultural, industrial and other workers. Education through part-time and correspondence courses should be given the same status as full-time education. Such facilities will smoothen transition from school to work, promote the cause of education and provide opportunities to the large number of people who have the desire to educate themselves further but cannot do so on a full-time basis.

(14) *Spread of Literacy and Adult Education.*—(a) The liquidation of mass illiteracy is necessary not only for promoting participation in the working of democratic institutions and for accelerating programmes of production, especially in agriculture, but for quickening the tempo of national development in general. Employees in large commercial, industrial and others concerns should be made functionally literate as early as possible. A lead in this direction should come from the industrial undertakings in the public sector. Teachers and students should be actively involved in organising literacy campaigns, especially as part of the Social and National Service Programme.

(b) Special emphasis should be given to the education of young practising farmers and to the training of youth for self-employment.

(15) *Games and Sports.*—Games and sports should be developed on a large scale with the object of improving the physical fitness and sportsmanship of the average student as well as of those who excel in this department. Where playing fields and other facilities for developing a nation-wide programme of physical education do not exist, these should be provided on a priority basis.

(16) *Education of Minorities.*—Every effort should be made not only to protect the rights of minorities but to promote their educational interests as suggested in the statement issued by the Conference of the Chief Ministers of States and Central Ministers held in August 1961.

(17) *The Educational Structure.*—It will be advantageous to have a broadly uniform educational structure in all parts of the country. The ultimate objective should be to adopt the 10+2+3 pattern, the higher secondary stage of two years being located in schools, colleges or both according to local conditions.

5. The reconstruction of education on the lines indicated above will need additional outlay. The aim should be gradually to increase the investment in education so as to reach a level of expenditure of 6 per cent of the national income as early as possible.

6. The Government of India recognizes that reconstruction of education is no easy task. Not only are the resources scarce but the problems are exceedingly complex. Considering the key role which education, science and research play in developing the material and human resources of the country, the Government of India will, in addition to undertaking programmes in the Central sector, assist the State Governments for the development of programmes of national importance where coordinated action on the part of the States and the Centre is called for.

7. The Government of India will also review, every five years, the progress made and recommend guidelines for future development.

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and Administrations of Union Territories and to all Ministries of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for Information.

G. K. CHANDIRAMANI,
Secretary to the Government of India.